www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-2* *Issue-5* *May 2025*

औपनिवेशिक काल में शाहाबाद क्षेत्र में शिक्षा का विकास स्तर

शिखा

शोध छात्रा, इतिहास विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

सारांश

औपनिवेशिक भारत में शिक्षा प्रणाली केवल ज्ञान के प्रसार का माध्यम नहीं थी, बल्कि वह एक सशक्त औजार थी, जिसके माध्यम से ब्रिटिश शासन ने सामाजिक संरचना, वर्गीय समीकरण और राजनीतिक चेतना को प्रभावित किया। बिहार के शाहाबाद क्षेत्र जिसमें वर्तमान भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिले सम्मिलित हैं– में शिक्षा का विकास इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही पाठशालाएँ, टोल, मदरसे और गुरुकुल जैसी संस्थाएँ सक्रिय थीं, जहाँ धार्मिक, नैतिक और परंपरागत ज्ञान का हस्तांतरण होता था। किंतु औपनिवेशिक शासन के आगमन के बाद इस व्यवस्था में गहरा परिवर्तन आया। ब्रिटिश सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों, जैसे 1835 की मैकोले नीति, 1854 का वुड्स डिस्पैच और 1882 का हंटर आयोग, ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विज्ञान पर बल दिया। शाहाबाद क्षेत्र में सरकारी और मिशनरी स्कूलों की स्थापना हुई, परंतु इनकी पहुँच मुख्यतः सवर्ण और संपन्न वर्गों तक सीमित रही। पिछड़े, दलित, मुस्लिम और महिला वर्ग इस नवाचार से वंचित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक शिक्षा नीति सामाजिक समावेशन के बजाय वर्गीय और जातीय असमानता को पोषित करती रही। हालाँकि इस प्रक्रिया में एक सीमित शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, जिसने प्रशासनिक सेवा, न्यायिक तंत्र और पत्रकारिता में प्रवेश पाया, किंतु यह वर्ग भी ब्रिटिश हितों के अनुकूल प्रशिक्षित था। शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज के बौद्धिक ढाँचे में परिवर्तन अवश्य आया, लेकिन यह परिवर्तन व्यापक, समावेशी या स्वदेशी नहीं कहा जा सकता। इस शोध पत्र में शाहाबाद क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार शिक्षा एक सामाजिक नियंत्रक शक्ति बनकर औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने का साधन बनी।

मुख्य–शब्द– औपनिवेशिक शिक्षा, शाहाबाद, पारंपरिक पाठशालाएँ, सामाजिक असमानता, मिशनरी स्कूल, शिक्षा नीति, ब्रिटिश शासन।

परिचय

भारत का औपनिवेशिक इतिहास केवल राजनीतिक दमन और आर्थिक शोषण की कहानी नहीं है, बल्कि यह शिक्षा जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से सांस्कृतिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। विशेषतः शिक्षा प्रणाली, जो कि समाज के निर्माण की धुरी होती है, औपनिवेशिक शासन में केवल ज्ञान के प्रसार का माध्यम नहीं रही, बल्कि सत्ता, वर्ग और जाति के संतुलन को नियंत्रित करने का एक औजार बन गई। ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई शिक्षा नीतियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि किस प्रकार शिक्षा को केवल एक सीमित प्रशासनिक वर्ग तैयार करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया गया। इस प्रक्रिया ने पारंपरिक ज्ञान व्यवस्था को पीछे धकेलते हुए एक नया औपनिवेशिक पाठ्यक्रम और प्रणाली स्थापित की, जिसका गहरा प्रभाव देश के सामाजिक–सांस्कृतिक ढांचे पर पड़ा। 1835 में लॉर्ड मैकोले द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की दिशा ही बदल दी। इस नीति के तहत भारतीय भाषाओं और पारंपरिक शिक्षा संस्थानों की उपेक्षा कर, अंग्रेजी भाषा और

पाश्चात्य ज्ञान को प्राथमिकता दी गई। वुड्स डिस्पैच (1854) और हंटर आयोग (1882) जैसे नीतिगत दस्तावेजों ने इस व्यवस्था को और अधिक औपचारिक रूप दिया। इन नीतियों के चलते केवल उन्हीं लोगों को शिक्षा का लाभ मिल सका, जो उच्च जातियों, विशेष रूप से ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार और अन्य प्रभुत्वशाली वर्गों से संबंधित थे। इस व्यवस्था में निचले जातियों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा से लगभग वंचित रखा गया। परिणामस्वरूप, शिक्षा का प्रसार न होकर वह वर्गीय और जातीय नियंत्रण का माध्यम बन गई। बिहार का शाहाबाद क्षेत्र, जिसमें वर्तमान भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिले आते हैं, औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था के इस संक्रमण काल का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से विद्या, संस्कृति और सामाजिक चेतना का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में यहाँ संस्कृत टोल, मदरसे, गुरुकुल और फारसी पाठशालाएँ संचालित थीं, जिनमें धर्म, न्यायशास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष एवं साहित्य की पढ़ाई होती थी। किंतु ब्रिटिश शासन में पारंपरिक शिक्षा संस्थानों को हतोत्साहित कर, अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों की स्थापना की गई। मिशनरी स्कूलों के माध्यम से ईसाई धर्म प्रचार और अंग्रेजी संस्कृति का प्रसार भी इस क्षेत्र में बढ़ा। हालांकि सासाराम, आरा, बक्सर जैसे शहरी क्षेत्रों में कुछ विद्यालय खुले, परन्तु वे भी उच्च जातियों और पुरुषों तक ही सीमित रहे।

शाहाबाद क्षेत्र में शिक्षा की इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का विश्लेषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र सामाजिक संरचना, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक उत्तराधिकार की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। यहाँ की सामाजिक बनावट में जातिगत भेद अत्यधिक प्रभावशाली रहा है, जिसने शिक्षा की पहुँच को भी प्रभावित किया। यही कारण है कि इस शोध का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि यह समझना है कि औपनिवेशिक नीतियाँ किस प्रकार एक क्षेत्र विशेष में शिक्षा के स्वरूप को नियंत्रित करती थीं। यह अध्ययन इस बात का विश्लेषण करता है कि किस हद तक ब्रिटिश शिक्षा नीतियों ने स्थानीय समाज पर प्रभाव डाला और कैसे सामाजिक विषमता को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से संरक्षित किया गया।

पूर्व–औपनिवेशिक काल में शाहाबाद की शिक्षा व्यवस्था

भारत में शिक्षा की परंपरा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रही है, और इसका प्रभाव देश के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। बिहार का शाहाबाद क्षेत्र (जिसमें आज के भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिले शामिल हैं) शिक्षा की परंपरा में विशेष स्थान रखता है। औपनिवेशिक शासन के पूर्व इस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था गहराई से भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई थी। यहाँ शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक मूल्यों और आत्मिक उन्नति का साधन मानी जाती थी। शाहाबाद क्षेत्र में उस समय प्रमुखतः चार प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएँ सक्रिय थींरू पाठशालाएँ, टोल, मदरसे और गुरुकुल। पाठशालाएँ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होती थीं, जहाँ छात्रों को व्याकरण, गणित, और व्यवहारिक धर्मशास्त्र सिखाया जाता था। ये पाठशालाएँ स्थानिक स्तर पर ग्रामीण समुदायों द्वारा चलाई जाती थीं और शिक्षकों को 'गुरु दक्षिणा' या अन्न/अनाज के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जाता था। टोल संस्कृत शिक्षा के केंद्र थे, जो ब्राह्मणों द्वारा चलाए जाते थे और जहाँ न्याय, वेद, मीमांसा, और साहित्य जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। ये शिक्षा संस्थान विशेष रूप से उन छात्रों के लिए होते थे जो विद्वत् वर्ग में स्थान प्राप्त करना चाहते थे। मदरसे मुस्लिम समुदाय के लिए ज्ञान के केंद्र थे, जहाँ कुरआन, हदीस, हिकमत, अरबी–फारसी साहित्य और गणित का अध्ययन कराया जाता था। बक्सर और आरा जैसे नगरों में कई प्रतिष्ठित मदरसे विद्यमान थे, जो न केवल धार्मिक बल्कि व्यवहारिक विषयों में भी शिक्षा प्रदान करते थे। वहीं, गुरुकुल प्रणाली विशेष रूप से हिंदू धार्मिक ग्रंथों और आचारशास्त्र पर केंद्रित होती थी, जिसमें छात्र गुरुओं के साथ निवास कर दीर्घकालीन शिक्षा प्राप्त करते थे। यह प्रणाली आत्म–अनुशासन, भक्ति, और तप के सिद्धांतों पर आधारित थी। इन संस्थाओं में पढ़ाए जाने वाले पारंपरिक विषयों में संस्कृत, फारसी, गणित, ज्योतिष, नैतिक शिक्षा, और आयुर्वेद प्रमुख थे। शिक्षा की पद्धति स्मृति–आधारित और शास्त्र–केन्द्रित थी, जहाँ पाठ कंठस्थ कराए जाते थे और शास्त्रार्थ (विवाद प्रतियोगिता) के माध्यम से छात्र की योग्यता की परीक्षा ली जाती थी। शिक्षक और शिष्य के मध्य गहरे आत्मीय संबंध होते थे, जो शिक्षण को केवल ज्ञान तक सीमित न रखकर आचरण और धर्म की ओर प्रेरित करते थे।

शिक्षा में वर्गीय और सामाजिक भागीदारी की बात करें तो, ब्राह्मण, कायस्थ और भूमिहार जैसे उच्च जातियों के लोग टोल और पाठशालाओं में प्रमुखता से भाग लेते थे। मुस्लिम समाज के शिक्षार्थी मदरसों में संख्या में अधिक थे। किंतु, यह भी सत्य है कि नीची जातियों, दलितों और महिलाओं को औपचारिक शिक्षा से लगभग बहिष्कृत रखा गया था। सामाजिक संरचना ऐसी थी कि शिक्षा अधिकार नहीं, विशेषाधिकार के रूप में विकसित

हुई। फिर भी, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समाज ने अर्धशिक्षा या कारीगरी से संबंधित ज्ञान (जैसे लिपिकीय कार्य या लेखन कला) के लिए वैकल्पिक व्यवस्था विकसित की थी। शाहाबाद क्षेत्र में यह समृद्ध और बहुपरतीय शिक्षा प्रणाली केवल ज्ञान–प्राप्ति तक सीमित न रहकर समाज के नैतिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को भी दिशा देती थी। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य मात्र जीविका नहीं था, बल्कि वह जीवन का मार्गदर्शन करने वाली प्रक्रिया मानी जाती थी। यही वह पारंपरिक व्यवस्था थी, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली ने धीरे–धीरे हाशिए पर ला खड़ा किया।

औपनिवेशिक शिक्षा नीतियाँ और उनका स्थानीय प्रभाव

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत में शिक्षा को केवल ज्ञान के प्रसार का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी सत्ता को मजबूत करने के एक औजार के रूप में प्रयोग किया। शिक्षा नीतियों के माध्यम से भारत की पारंपरिक ज्ञान पद्धति को हतोत्साहित कर पश्चिमी विचारधारा को आरोपित किया गया। यह परिवर्तन विशेष रूप से उन क्षेत्रों में और भी प्रभावी रहा जो पहले से ही सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध थे, जैसे कि बिहार का शाहाबाद क्षेत्र। शाहाबाद में शिक्षा प्रणाली पर इन नीतियों का गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा, जिसने वहाँ के सामाजिक ढाँचे, भाषाई स्वरूप और वर्गीय संरचना को बदलकर रख दिया। 1835 में लॉर्ड मैकोले की शिक्षा नीति ने भारत की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था पर सबसे पहला और निर्णायक प्रहार किया। मैकोले का मत था कि भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा को लागू किया जाना चाहिए ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो मानसिकता से अंग्रेज़ हो लेकिन नस्ल और रंग से भारतीय रहे। उन्होंने भारतीय भाषाओं और पारंपरिक विषयों को अनुपयोगी बताते हुए अंग्रेजी को ही शिक्षण का एकमात्र प्रभावी माध्यम माना। इस नीति ने शाहाबाद सहित संपूर्ण बिहार में संस्कृत, फारसी, और अरबी जैसी शैक्षणिक भाषाओं को धीरे–धीरे दरकिनार कर दिया। सके पश्चात 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसने भारत में एक संरचित शिक्षा तंत्र स्थापित करने की बात कही। वुड्स डिस्पैच के माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए पृथक–पृथक संस्थानों की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षकों के प्रशिक्षण, और छात्रवृत्ति जैसे बिंदुओं पर बल दिया गया। शाहाबाद क्षेत्र में इसका प्रभाव यह हुआ कि आरा, सासाराम, और बक्सर जैसे कस्बों में सरकारी विद्यालय स्थापित होने लगे। किंतु यह शिक्षा केवल विशेष वर्गों तक सीमित रही और जातीय आधार पर भेदभाव जारी रहा। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना हुई, जिसने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों के हवाले करने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा एक सीमित वर्ग को ही उपलब्ध है और जनसामान्य इससे वंचित है। आयोग की सिफारिशों के बाद शाहाबाद क्षेत्र में कुछ स्थानीय विद्यालय खुलने लगे, लेकिन संसाधनों की कमी और सामाजिक अवरोधों के कारण इनमें वांछनीय प्रगति नहीं हो पाई। इन नीतियों के तहत शाहाबाद में सरकारी के साथ–साथ मिशनरी स्कूलों की भी स्थापना हुई। मिशनरियों ने शिक्षा को धार्मिक प्रचार का माध्यम बनाया और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए विद्यालयों की स्थापना की। बक्सर और रोहतास जिलों में मिशनरी स्कूलों के माध्यम से गरीब और निचली जातियों के बच्चों को नाम मात्र की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें धार्मिक ग्रंथ और अंग्रेजी बाइबिल प्रमुख होते थे। यद्यपि इन संस्थानों ने कुछ हद तक साक्षरता बढ़ाई, परन्तु उनका उद्देश्य पूर्णतः धार्मिक और राजनीतिक था। शिक्षा में भाषाई परिवर्तन भी इस काल की एक विशेष प्रक्रिया रही। पहले जहाँ संस्कृत, अरबी और फारसी शिक्षा की प्रमुख भाषाएँ थीं, वहीं अब अंग्रेज़ी को माध्यम भाषा बना दिया गया। यह परिवर्तन केवल भाषाई नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक विस्थापन भी था। शाहाबाद के परंपरागत शिक्षित वर्ग, जो संस्कृत या फारसी में पारंगत थे, अब शिक्षा तंत्र से बाहर हो गए। अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व ने एक नए प्रभुत्वशाली वर्ग को जन्म दिया, जो प्रशासनिक सेवाओं और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगा। इससे शिक्षा का लोकतांत्रीकरण नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक विषमता और बढ़ गई।

औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों का प्रभाव केवल संस्थागत परिवर्तनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने समाज की चेतना, भाषा, वर्गीय संरचना और ज्ञान की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। शाहाबाद क्षेत्र की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जो स्थानीय समाज की आवश्यकताओं और संस्कृति से जुड़ी थी, एक बाह्य थोपे गए ढांचे में परिवर्तित हो गई। यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि शिक्षा की ये नीतियाँ केवल शैक्षणिक सुधार नहीं थीं, बल्कि एक सूक्ष्म सामाजिक–राजनीतिक नियंत्रण का हिस्सा थीं, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक सत्ता को सुदृढ़ करना था।

शाहाबाद क्षेत्र में विद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना

औपनिवेशिक शासनकाल में भारत के अनेक क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना अंग्रेजों द्वारा एक विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्य के साथ की गई। बिहार का शाहाबाद क्षेत्रकृजिसमें आज के भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले सम्मिलित हैं– ऐसा ही एक भूगोलिक क्षेत्र था, जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था से आधुनिक शिक्षा की ओर संक्रमण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभरा। यहाँ विद्यालयों और संस्थानों की स्थापना का क्रम 19वीं सदी के मध्य से आरंभ होकर 20वीं सदी तक धीरे–धीरे विस्तृत होता गया। शाहाबाद के प्रमुख नगरों बक्सर, आरा, सासाराम और डेहरी ने इस बदलाव में अग्रणी भूमिका निभाई। बक्सर में 1860 के दशक में एक सरकारी विद्यालय की स्थापना की गई, जो तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा नीति के अनुरूप था। यह विद्यालय प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षकों की नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने हेतु आरंभ किया गया था। आरा, जो शाहाबाद जिले का प्रमुख शहरी केंद्र था, वहाँ 1870 में 'शाहाबाद जिला स्कूल' की स्थापना हुई। यह विद्यालय कालांतर में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और इंटरमीडिएट स्तर तक विस्तारित हुआ। सासाराम में मिशनरी संगठनों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए, जहाँ बाइबिल पढ़ाने के साथ–साथ अंग्रेजी, गणित और भूगोल जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। डेहरी में रेलवे के विस्तार के साथ ही वहाँ शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता बढ़ी और 1890 के दशक में रेलवे कर्मियों के बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल खोला गया।

इस क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का ढाँचा औपनिवेशिक प्रशासन की नीतियों के अनुरूप विकसित हुआ। प्राथमिक शिक्षा को अक्सर स्थानीय निकायों या मिशनरियों के अधीन रखा गया, जिनमें पढ़ाई की भाषा उर्दू या हिन्दी होती थी। माध्यमिक शिक्षा मुख्यतः सरकारी नियंत्रण में थी और इसमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। उच्च शिक्षा की स्थिति तुलनात्मक रूप से दुर्बल रही। अधिकांश छात्र उच्च शिक्षा के लिए पटना, वाराणसी या कलकत्ता जैसे शहरों की ओर प्रवृत्त होते थे। बावजूद इसके, सासाराम और आरा में इंटर कॉलेज स्तर के कुछ संस्थानों की स्थापना 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में हो चुकी थी।

सरकारी बनाम निजी (मिशनरी) शिक्षण संस्थानों की तुलना करें तो यह स्पष्ट होता है कि सरकारी विद्यालयों में प्रवेश सीमित और विशिष्ट वर्ग तक केंद्रित था। इन विद्यालयों का उद्देश्य अंग्रेजी पढ़े–लिखे क्लर्क, मुंशी और निचले स्तर के प्रशासनिक अधिकारी तैयार करना था। दूसरी ओर मिशनरी स्कूलों ने अपेक्षाकृत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन उनका उद्देश्य शिक्षा से अधिक धर्म–प्रसार था। मिशनरी संस्थानों में छात्रों को मुख्यतः बाइबिल आधारित शिक्षण सामग्री पढ़ाई जाती थी और उन्हें ईसाई धर्म के प्रति प्रेरित किया जाता था। कई मिशनरी विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग कक्षाएँ भी चलाई जाती थीं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से एक नया प्रयास था। विद्यालयों की स्थापना के बावजूद शाहाबाद क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार व्यापक नहीं हो पाया। जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर शिक्षा की पहुँच सीमित रही। भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ समुदायों के छात्र इन संस्थानों में अधिक संख्या में देखे जाते थे, जबकि दलित और पिछड़ी जातियों के लिए यह शिक्षा प्रणाली लगभग असुलभ थी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या अत्यंत सीमित थी, जिससे क्षेत्रीय विषमता और भी बढ़ गई। औपनिवेशिक काल में शाहाबाद क्षेत्र में विद्यालयों और संस्थानों की स्थापना एक योजनाबद्ध प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसका मूल उद्देश्य भारतीय समाज में एक शिक्षित वर्ग को उत्पन्न करना था जो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार हो। इन संस्थानों के माध्यम से भारतीय समाज में न केवल नई शिक्षा प्रणाली का प्रवेश हुआ, बल्कि सामाजिक संरचना में भी गहरा परिवर्तन आया, जो आज भी देखा जा सकता है।

औपनिवेशिक शिक्षा के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में लागू की गई शिक्षा प्रणाली ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक ढांचे में दूरगामी परिवर्तन उत्पन्न किए। शाहाबाद क्षेत्र, जो बिहार के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक माना जाता है, इस संक्रमण प्रक्रिया का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव न केवल संस्थागत रूप में देखा गया, बल्कि यह समाज की चेतना, विचारधारा और सामाजिक गतिशीलता को भी प्रभावित करने में सफल रही। औपनिवेशिक शिक्षा ने जहाँ एक ओर आधुनिक प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप एक नया शिक्षित वर्ग तैयार किया, वहीं दूसरी ओर इसने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और सामाजिक संरचना को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख सकारात्मक पक्ष यह रहा कि इसने

भारत में एक संगठित प्रशासनिक वर्ग के निर्माण की आधारशिला रखी। लॉर्ड मैकोले की 'डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी' के अंतर्गत अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षित एक ऐसा वर्ग तैयार किया गया, जो औपनिवेशिक सत्ता की सेवा के लिए प्रशिक्षित था। शाहाबाद क्षेत्र में आरा, सासाराम, और बक्सर जैसे शहरी केंद्रों में स्थापित स्कूलों और कॉलेजों से पढ़े हुए युवाओं को राजस्व विभाग, न्यायिक तंत्र, रेलवे, डाक सेवा और पुलिस प्रशासन में नियुक्तियाँ प्राप्त हुईं। इसने समाज में 'नौकरी' को प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाया और शिक्षा को एक व्यावसायिक साधन के रूप में स्थापित किया। यह प्रशासनिक वर्ग, भले ही ब्रिटिश सत्ता का सहयोगी था, लेकिन उसने भारतीय समाज में आधुनिक राज्य प्रणाली की नींव डालने में भूमिका निभाई।

इसके अतिरिक्त, औपनिवेशिक शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि इसने भारत में पुनर्जागरण और राष्ट्रवादी चेतना को गति दी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय विद्यार्थियों ने यूरोपीय इतिहास, राजनीतिक सिद्धांत, मानवाधिकार और स्वतंत्रता जैसे आधुनिक विचारों से परिचय प्राप्त किया। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और बाद में गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष जैसे नेता इसी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से प्रभावित होकर सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत बने। शाहाबाद क्षेत्र में भी शिक्षित युवाओं में ब्रिटिश सत्ता के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी बढ़ी। पत्रकारिता, सभाएँ, राजनीतिक जागरूकताकृइन सभी का मूल स्रोत औपनिवेशिक शिक्षा ही रही। हालांकि, इन सकारात्मक पक्षों के समानांतर औपनिवेशिक शिक्षा के कई नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह रहा कि इस प्रणाली ने भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को क्रमशः नष्टप्राय कर दिया। संस्कृत टोल, फारसी मदरसे, गुरुकुलों और पारंपरिक पाठशालाओं का सामाजिक महत्व समाप्त होने लगा। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने से भारतीय भाषाएँ और उनसे जुड़ा साहित्य, दर्शन, चिकित्सा, और गणित का विशाल ज्ञान उपेक्षित रह गया। शाहाबाद क्षेत्र में ऐसे कई गुरुकुल और मदरसे थे जो कभी सांस्कृतिक चेतना के केंद्र थे, वे शिक्षा नीति में बदलाव के बाद निष्क्रिय हो गए। इसने न केवल ज्ञान परंपरा का विनाश किया, बल्कि एक सांस्कृतिक अस्मिता को भी धूमिल कर दिया। औपनिवेशिक शिक्षा ने समाज में एक नया वर्गीय विभाजन भी उत्पन्न कियाकृअंग्रेजी शिक्षित और अशिक्षित वर्ग के बीच। यह विभाजन केवल भाषाई नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रशासनिक पहुँच और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक बन गया। शाहाबाद जैसे क्षेत्र में यह विभाजन बहुत स्पष्ट रूप में सामने आया, जहाँ एक ओर अंग्रेजी स्कूलों से निकले युवाओं को प्रशासन में स्थान मिला, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक पंडित, मौलवी और कारीगर वर्ग शिक्षा के नए ढांचे से कट गए।

निष्कर्षतः औपनिवेशिक शिक्षा नीति एक मिश्रित प्रभाव की वाहक रही। एक ओर इसने आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली और राष्ट्रवादी चेतना को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत की प्राचीन बौद्धिक परंपरा को पीछे धकेलकर ज्ञान के स्वरूप को औपनिवेशिक दृष्टिकोण में सीमित कर दिया। शाहाबाद क्षेत्र इस संक्रमण का जीवंत उदाहरण है, जहाँ शिक्षा का लाभ उठाने वाले वर्गों ने सामाजिक उन्नयन पाया, लेकिन इसके साए में पारंपरिक समाज का बड़ा हिस्सा अंधकार में ही रह गया।

निष्कर्ष

शाहाबाद क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन के प्रभावों का अध्ययन एक जटिल, बहुआयामी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण की माँग करता है। यह शोध उन सामाजिक, शैक्षणिक, और वैचारिक परिवर्तनों का समेकित मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा प्रणाली में उत्पन्न हुए और जिनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। शिक्षा का स्वरूप इस काल में केवल ज्ञान के स्थानांतरण का साधन नहीं रहा, बल्कि यह एक गहन सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन गया। औपनिवेशिक विरासत और वर्तमान शैक्षिक ढाँचे पर इसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज में गहराई से विद्यमान है। आज भी भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, परीक्षा–केंद्रित प्रणाली, रोजगारोन्मुखी दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम की औपनिवेशिक संरचना यथावत बनी हुई है। शाहाबाद क्षेत्र में भी वर्तमान विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक परंपराओं में ब्रिटिश कालीन प्रभावों की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है। अनेक सरकारी विद्यालय आज भी उन्हीं इमारतों में संचालित हो रहे हैं, जिनकी नींव औपनिवेशिक काल में रखी गई थी। यह प्रणाली एक ओर आधुनिकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अवसर प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय ज्ञान, भाषाई विविधता और सामाजिक समावेशन को अब भी सीमित करती है। अंततः यह कहा जा

सकता है कि औपनिवेशिक काल में शाहाबाद क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए, उन्होंने न केवल तत्कालीन सामाजिक संरचना को पुनर्परिभाषित किया, बल्कि आज के शैक्षणिक ढांचे की आधारशिला भी रखी। शिक्षा केवल एक औपचारिक प्रणाली न होकर सामाजिक चेतना, वर्गीय संरचना और राजनीतिक दिशा को निर्धारित करने वाला साधन बन गई, जिसकी छाया आज भी हमारी शिक्षानीति और समाज व्यवस्था में देखी जा सकती है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, जे.सी. (2009). डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इन्डिया, शिप्रा प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. प्रसाद रमेश, (2016), बिहार इतिहास कला एवं संस्कृति, पार्वती प्रकाशन, पटना।
3. ठाकुर, ए.एस. एवं वरबौल, एस. (2008). डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इन्डिया, शिप्रा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. पाटी, बिस्वमोय, एवं सिंह, लता (सं.) (2014). औपनिवेशिक और समकालीन बिहार एवं झारखंड, ट्यूलिप पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
5. वासु, ए. (1974). द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड पालीटिकल डेवलपमेंट इन इन्डिया, 1898–1920, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
6. कौलेश्वरराय (2018) बिहार का इतिहास, किताब महल, दिल्ली।
7. वासु, बी.डी. (1989). हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इन्डिया, नई दिल्लीः कॉसमो पब्लिकेशन।
8. झा, नरेंद्र। (2014). बिहार और बिहारी का निर्माण– औपनिवेशिकता, राजनीति और आधुनिक भारत में संस्कृति (1870–1912) मनोहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
9. झा, जटा शंकर (1979) बिहार में शिक्षा (1813–1859)। काशी प्रसाद जयसवाल शोध संस्थान, पटना।
10. कुमार, कृष्ण. (1991). द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
11. सत्यनारायण (सं.) (2011) औपनिवेशिक भारत में शिक्षाः ऐतिहासिक अंतर्दृष्टियाँ, मनोहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
12. नरूला, एस. एव ं नायक, जे.पी. (1974). ए स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इन्डिया (1800–1973). छठा संस्करण, मैकमिलन इन्डिया, नई दिल्ली।

Cite this Article-

'शिखा', 'औपनिवेशिक काल में शाहाबाद क्षेत्र में शिक्षा का विकास स्तर', *Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:05, May 2025.*

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i5009

Published Date- 08 May 2025